Newspaper Clips

April 23, 2011

Navbharat Times ND 23/04/2011 P-5

आज आईआईटी दिल्ली में दिखेंगे

छोटे-छोटे चमत्कार...

आईआईटी दिल्ली कैंपस में आज ग्रैंड ओपन हाउस है, यहां आपको स्टूडेंट्स के बनाए 250 से ज्यादा साइंस व डिजाइन प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपकी भी साइंस में दिलचस्पी है तो पहुंच जाइए आज आईआईटी। खासकर बच्चों के लिए साइंस को करीब से जानने का यह बहुत ही अच्छा मौका है। खालिद अमीन ने शुक्रवार को आईआईटी पहुंचकर आज दिखाए जाने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया :

3डी सांप-सीढ़ी प्लस...

आजकल 3डी का जमाना है तो अरुणनिवास और जननी ने भी सांप-सीढ़ी का 3डी गेम तैयार कर लिया। बांस से बने इस स्टेशन में गेम खेलते हुए आपको ज्यादा रियल फील आती है। यही नहीं, इस स्टेशन में सांप-सीढ़ी के अलावा सात और गेम भी इनबिल्ट हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बड़े भी इसे देखकर खेलने को मचल उठेंगे।

प्लेटें धुलेंगी नॉन स्टॉप

हॉस्टल में रोजाना सैकड़ों की तादाद में गंदी प्लेटों को देखकर इन आईआईटी स्टूडेंट्स को यह आइडिया आया। आम डिशवॉशर में गंदी प्लेटों को लोड करना होता है लेकिन इस डिशवॉशर में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई है कि स्टूडेंट्स बस अपनी प्लेटों को एक जगह रख दें, यह मशीन खुद इन प्लेटों को धो डालेगी, और वह भी नॉन स्टॉप। इस टीम में शामिल हैं धीरेंद्र, विनायक, राजेश और पंकज।

बांस का इलेक्ट्रिक गिटार

कॉलेज और गिटार का बहुत पुराना रिश्ता है। अब इलेक्ट्रिक गिटार का जमाना है लेकिन यह काफी महंगा होता है,। किरण, सचिन और विपिन की टीम ने बांस से इलेक्ट्रिक गिटार बनाया है जिसकी कीमत नॉर्मल इलेक्ट्रिक गिटार से आधी से भी कम होगी। कुछ जरूरी पार्ट्स को छोड़कर पुरा गिटार बांस से बना है और दिखने में भी काफी कूल है।

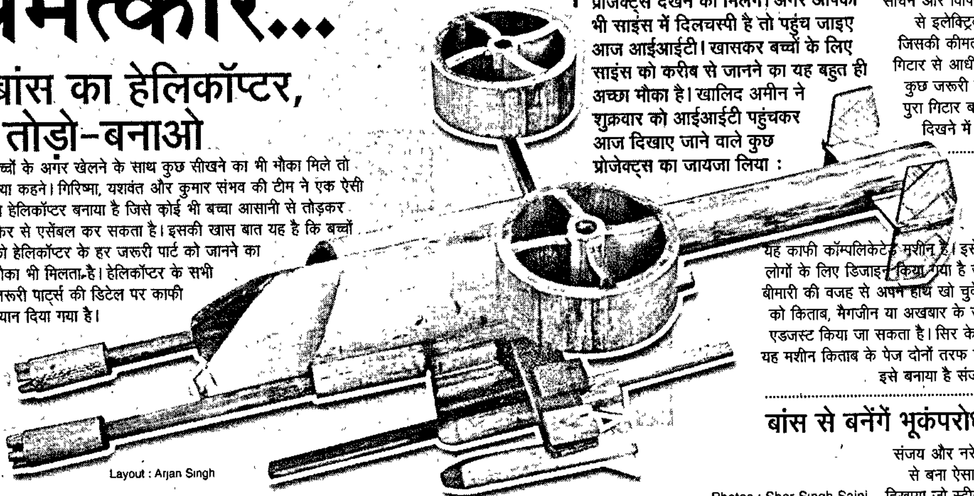

बांस का हेलिकॉप्टर, तोड़ो-बनाओ

बच्चों के अगर खेलने के साथ कुछ सीखने का भी मौका मिले तो क्या कहने। गिरिष्मा, यशवंत और कुमार संभव की टीम ने एक ऐसी ही हेलिकॉप्टर बनाया है जिसे कोई भी बच्चा आसानी से तोड़कर फिर से एसेंबल कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि बच्चों को हेलिकॉप्टर के हर जरूरी पार्ट को जानने का मौका भी मिलता है। हेलिकॉप्टर के सभी जरूरी पार्ट्स की डिटेल पर काफी ध्यान दिया गया है।

पेज टर्निंग मशीन

यह काफी कॉम्पलिकेटेड मशीन है। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी हादसे या बीमारी की वजह से अपने हाथ खो चुके हैं। इसके साइज को किताब, मैगजीन या अखबार के साइज से हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सिर के जरा से मूवमेंट से यह मशीन किताब के पेज दोनों तरफ से पलट सकती है। इसे बनाया है संजीव और गुंजीत ने।

Layout : Arjan Singh

कपड़े सूखेंगे फटाफट

गरिमा, मीनाक्षी और मंजुलता ने इस मशीन को डिजाइन किया है। ऊपर लगे रिंग में कपड़े टांगकर मोटर ऑन कर दीजिए और मशीन दोनों दिशाओं में घूमकर फटाफट कपड़े सुखा देगी। जिन लोगों के पास कपड़े सुखाने की जगह नहीं है वे अपनी बालकनी में इस छोटी से मशीन को लगा सकते हैं। इसमें टाइमर भी लगा है जिसमें टाइम सेट करके आप दूसरे काम कर सकते हैं।

बांस की साइकल

साइकल तो वैसे भी इको फ्रेंडली होती है लेकिन इस साइकल को सुपर इको फ्रेंडली कहा जा सकता है। द्विपायन और शुभम की टीम ने इस साइकल को और हल्का बनाने के लिए इसमें जहां मुमकिन हो सका बांस का इस्तेमाल किया है। इस एक्सपेरिमेंट से बिना साइकल की मजबूती कम हुए इसे हल्का और सस्ता बनाना मुमकिन हुआ है।

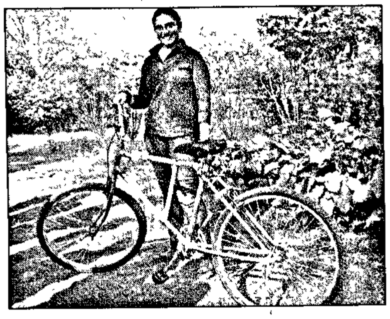

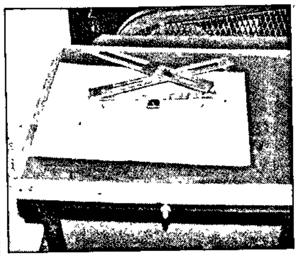

कमाल का ज्यॉमेट्री बाक्स

यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से ज्यॉमेट्री से जुड़े सभी डायग्राम बनाए जा सकते हैं, इसके साथ आपको कोई भी दूसरा एपरेटस साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। इसकी सबसे खास बात है कि इससे ज्यॉमेट्री से जुड़े पैराबोला और इलिप्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं जो कोई भी दूसरा एपरेटस ड्रॉ नहीं कर सकता है। इसे डिजाइन किया है मयंक और चालुक्य की टीम ने।

बांस से बनेंगें भूकंपरोधी मकान

Photos : Sher Singh Saini

संजय और नरेश में हमें यहां बांस से बना ऐसा बिल्डिंग मैटिरियल दिखाया जो स्टील की तरह मजबूत लेकिन काफी सस्ता है। इसके काफी हल्का होने की वजह से भूकंप में बिल्डिंग को नुकसान भी नहीं होगा। यहां बांस के ऐसे पिलर दिखे जिनपर पूरी बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती है। पल्लवी और अल्शलेषा ने बांस से अंडे रखने का एक ऐसा बॉक्स तैयार किया जिसमें अंडे सेफ रहते हैं। उन्होंने बांस की टॉर्च और घड़ी भी बनाई है।

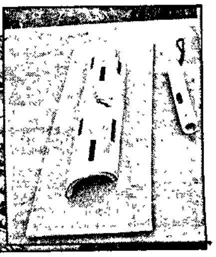

Financial Express ND. 23.04.11, P-1

Qualified faculty eludes engineering colleges

■ With a huge shortfall of PhD teachers, most new colleges are forced to opt for less experienced and trained staff

Diksha Dutta &
Kirtika Suneja
New Delhi, Apr 22

ENGINEERING colleges in the country, especially those in the minor league, may be popping up like mushrooms and even churning out graduates by the thousands, but when it comes to faculty quality, most colleges are forced to make do with relative freshers who do not even hold a PhD.

Consider this: Since 2008, the number of engineering colleges in the country has almost doubled from 1,668 to 3,241, and along with it the shortage of PhD-holders has also gone up from 54,839 in 2008-09 to 72,524 in 2010-11, according to figures from the ministry of human resource development.

This shortage is being felt acutely by these new colleges, which have difficulty attracting experienced staff. For instance, the Dehradun Institute of Technology (DIT) and Delhi Technological University (previously the Delhi College of Engineering) both have 200 faculty members, but while over 50% of DTU staff hold PhDs, being among the top ten tech colleges in India, DIT has only 25% PhDs.

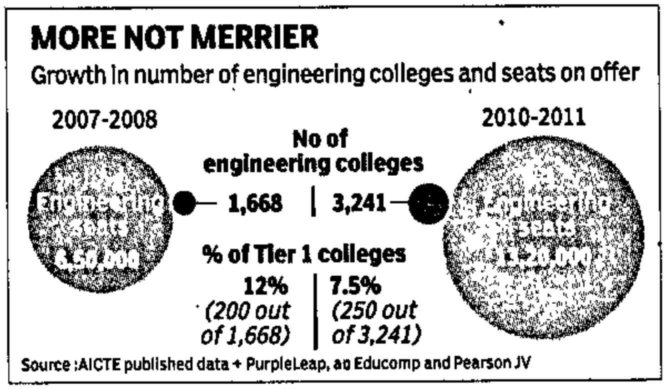

DIT director Krishna Kumar pleads helplessness. "It is difficult to attract experienced teachers given the numerous opportunities they have these days. So we are forced to opt for less experienced and qualified teachers. Currently we have just 20-30% senior teachers," he says.

And when it comes to top colleges, they are not ready to compromise on qualifications. "We do not hire plain BTech graduates and the minimum qualification required is MTech or its equivalent," says a DTU official.

Interestingly, there is a shortfall of faculty holding MTech degrees too. The number of MTechs required in engineering colleges has significantly increased from 90,000 in 2008 to approximately 120,000 in 2010. Because of this, regulator AICTE allows BTechs also to teach, but on the condition that they complete their MTech within three years.

"The average age of teachers with a BTech is around 22 years and with a PhD is 27 years. Why would a PhD-holder go to a smaller town to teach when he is in demand in a metro city?" reasons an AICTE official.

Agrees Amit Bansal, CEO at PurpleLeap, an Educomp and Pearson joint venture, "There is a marked difference in the experience of faculty of top-rung colleges and the rest. While the average faculty experience in top colleges is between 10 and 15 years, the average faculty experience in other colleges is 0-5 years."

Hindustan Times
23/04/2011 P-8

GOLD COINS FOR STAFF BENEFIT, NO CORRUPTION, SAYS IIT MADRAS

ht FOLLOW-UP

Charu Sudan Kasturi
charu.kasturi@hindustantimes.com

NEW DELHI: Gold coins offered to employees and alleged violations of government rules by the Indian Institute of Technology Madras were "human" gestures and did not involve any corruption, IIT Director MS Ananth said on Friday.

"The gold coins were financed through the IIT's corpus fund and we did not use government funds," Ananth told HT, responding to protests by a section of the institute faculty over the IIT's decision to award all 1500 employees gold coins at a time it is struggling to pay salaries and scholarships. "There was no hanky panky," he claimed.

Many within the IIT have questioned the move — reported first by HT on April 21 — calling the award a "waste of funds" the IIT could instead use to get financial autonomy.

Documents accessed by HT show that the Principal Auditor General of Tamil Nadu has found the IIT responsible for causing the public a loss of ₹7 crore by violating government pension rules and illegally subsidising power supply to faculty.

But Ananth on Friday said both the alleged pension violations and move to award gold coins were based on past precedents set by IITs. When told that IIT Bombay and Kharagpur were pulled up for audit queries, Ananth accepted that government had raised concerns over such moves in the past.

Ananth found "unique" ways to repeatedly allow faculty to benefit from both the Central Provident Fund Scheme and a Pension Scheme — when all government employees can benefit from only one, the auditor has said, slamming the IIT.

Dainik Bhaskar ND.
23.04.11, P-7

मैनेजमेंट फंडा

आईआईटी जैसे और भी हों सिस्टम

बीते 10 अप्रैल, रविवार को देश के सभी सोलह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) आयोजित की गई। इन आईआईटी संस्थानों में नया-नया खुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इस बेहद मुश्किल परीक्षा में 4,85,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनके लिए कुल मिलाकर 9,600 सीटें उपलब्ध हैं। यानी इस परीक्षा में महज 2 फीसदी परीक्षार्थी ही सफल होंगे, जिन्हें दाखिले की पात्रता मिलेगी। इसका मतलब है कि बाकी बचे 4,75,400 छात्रों के आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिले के सपने बिखर जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा के लिए उन्होंने कम से कम दो साल तक कड़ी मेहनत की होगी और कोचिंग कक्षाओं में लाखों रुपए खर्च किए होंगे। इतना ही नहीं, आईआईटी के प्रति दीवानगी के चलते बारहवीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ उनकी सेहत भी प्रभावित हुई होगी।

एन रघुरामन

गौरतलब है कि शुरुआत में पचास के दशक में सिर्फ पांच आईआईटी संस्थान बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और खड़गपुर में खोले गए थे। बाद में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों के लिहाज से गुवाहाटी में भी एक संस्थान खोला गया और इसके कुछ समय बाद रुड़की यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड होते हुए सातवें-आईआईटी के रूप में स्थापित हो गई। ये सातों आईआईटी संस्थान कई सालों तक अच्छा काम करते रहे और 'ब्रांड-आईआईटी' का ग्लैमर व मार्केट वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रहा।

लेकिन वर्ष 2009 के आम चुनाव के एक साल पहले मानो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कोई दैवीय बोध हुआ और इस विभाग के मंत्री ने देश के अलग-अलग राज्यों में आठ और आईआईटी संस्थान खोलने की घोषणा कर दी। इस तरह गुजरात के गांधीनगर, ओडिशा के भुवनेश्वर, बिहार के पटना, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, मध्य प्रदेश के इंदौर, हिमाचल प्रदेश के मंडी, राजस्थान के जोधपुर और पंजाब के रोपड़ में आईआईटी संस्थान खुल गए। बहरहाल, इन संस्थानों के लिए फैकल्टीज का इस कदर अभाव है कि 'वेटरन' प्रोफेसरों को 68 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं किया जा रहा है। विडंबना यह है कि इन त्वरित प्रयासों के वांछित नतीजे नहीं मिले और आज वर्ष 2011 में भी जेईई में सफलता की दर वही 2 फीसदी पर अटकी हुई है। इस परीक्षा से जुड़ी बेहद कड़ी प्रतिस्पर्द्धा को थोड़ा कम करने का एक तरीका यह है कि आनुपातिक रूप से कम छात्रों को जेईई में बैठने की इजाजत दी जाए और इसे 1,00,000 जैसे किसी तार्किक आंकड़े तक सीमित कर दिया जाए। इसके लिए छात्रों की वरीयता तय करने के लिहाज से अलग से कोई प्रणाली अपनाई जा सकती है। इससे तकरीबन 10,000 सीटों की उपलब्धता के साथ इस टेस्ट में बैठने वाले 10 फीसदी छात्रों को दाखिले की पात्रता मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। हमें आईआईटी-जेईई में इस 98 फीसदी फेल्योर सिस्टम को बदलने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। यदि हम इसे अभी नहीं रोक सके तो जल्द ही यह बाकी देश के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाएगी।

raghu@bhaskarnet.com

फंडा यह है कि हमें देश में आईआईटी सिस्टम जैसे और भी सिस्टम तैयार करने होंगे, ताकि इनमें प्रतिस्पर्द्धा कम हो और छात्रों को भी विकल्प मिल सके।

Times Of India ND 23/04/2011 P-21

The new age of giants

Plans to build the world's largest radio telescope are moving ahead, along with projects to build two more new giant science instruments

Square Kilometer Array

Construction **start 2016**

Thousands of coordinated radio dishes centered on site in southern Africa or Australia

Total effective antenna area **1 sq km**

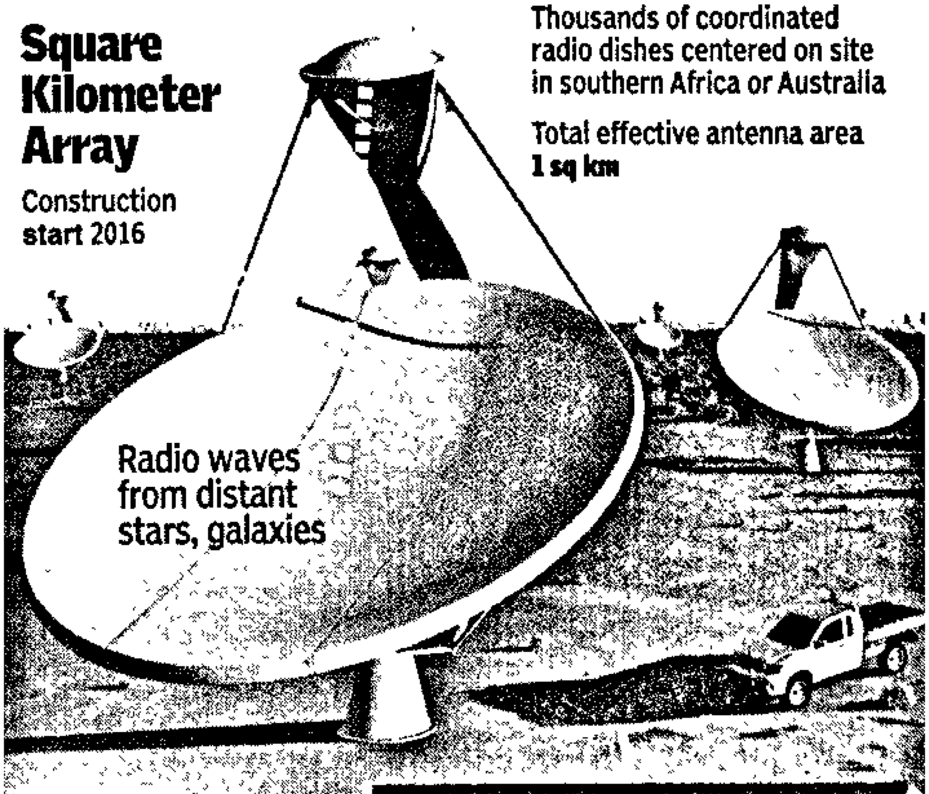

Webb Space Telescope

Will orbit sun staying **1.5 million km from Earth**

Will collect infrared light with cooled detectors

Launch 2014 or later

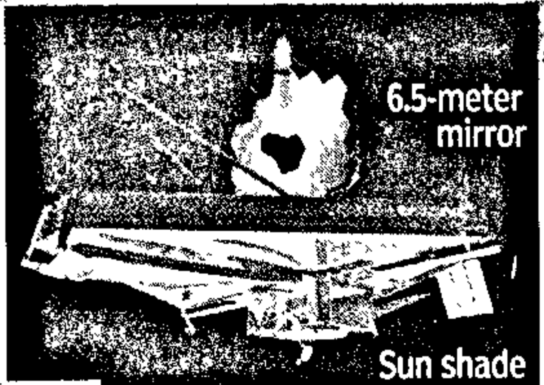

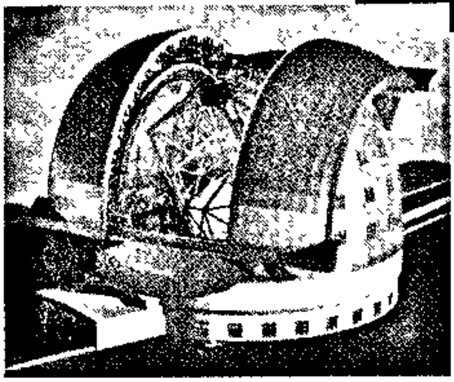

European Extremely Large Telescope

42 m diameter mirror; to be built in Chile

Completion 2018

Source: European Space Agency, NASA, Jodrell Bank Observatory
Graphic: Helen Lee McComas © 2011 MCT

Publication: The Times Of India Delhi;Date: Apr 23, 2011;Section: Times Global;Page: 23;

Restricted entry: UK rolls out tough student visa norms

London: Tough new rules applicable for students from India and other non-European Union countries have came into effect as part of the David Cameron government's promise to prevent abuse of the visa system and substantially reduce immigration during its term in office.

New rules include tougher entrance criteria, limits on work entitlements and the closure of the post-study work route, which was popular among self-financing students from India

The new rules include tougher entrance criteria, limits on work entitlements and the closure of the post-study work route, which was popular among self-financing students from India.

From April 2012, any institution wanting to sponsor students will need to be classed as a Highly Trusted sponsor, and will need to become accredited by a statutory education inspection body by the end of 2012.

The system until yesterday did not require this, and allowed many poor-quality colleges to become sponsors.

Students coming to study at degree level will need to speak English at an 'upper intermediate' level, rather than the current 'lower intermediate' requirement.

Immigration officials will be able to refuse entry to students who cannot speak English without an interpreter, and who therefore do not meet the minimum standard.

Students at universities and publicly funded further education colleges will retain their current work rights, but all other students will have no right to work. PTI